म्यूचुअल फंड्स के पास बिना दावे के 2,500 करोड़ रुपए : निवेशक या नॉमिनी तक ये पैसा पहुंचाने के लिए सेबी के साथ मिलकर काम कर

नई दिल्ली ।

म्यूचुअल फंड्स के पास बगैर दावे के करीब 2,500 करोड़ रुपए के डिविडेंड और यूनिट्स पड़े हैं। म्यूचुअल फंड्स के संगठन (एम्फी) के मुताबिक, इसमें से करीब 1,600 करोड़ रुपए बगैर दावे वाले लाभांश और शेष बिना दावे से जुड़ी बिकवाली से संबंधित हैं। एम्फी के सीईओ एन एस वेंकटेश ने कहा कि संगठन ने ये सुनिश्चित करने के लिए बाजार नियामक सेबी के साथ लगातार काम किया है कि ये राशि सही मालिकों के हाथों में पहुंच जाए। उन्होंने कहा, 'सेबी ने एम्फी को ये सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि निवेशक या उनके नॉमिनी या वारिस तक ये पैसे पहुंच जाएं। हम इस संबंध में सेबी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ये आंकड़ा निकट भविष्य में काफी कम हो जाएगा।' वेंकटेश ने कहा कि फंड हाउस इन निवेशकों से ई-मेल आईडी और पैन से जुड़े फोन नंबरों के जरिए संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं।

कंडीशन : बगैर दावे की राशि इन सूरतों में - म्यूचुअल फंड के पास पड़ी रकम ऐसी सूरत में बगैर दावे की मानी जाती है, जब फंड हाउस ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन माध्यमों से भी निवेशकों को लाभांश और रिडम्पशन पेमेंट करने में विफल रहा हो। इसका एक कारण संबंधित बैंक खातों का बंद होना भी है। सेबी के नियमों के मुताबिक, ऐसी राशि लिक्विड या ओवरनाइट जैसी छोटी अवधि की डेट स्कीम्स में रखी जाती है।

अनुमान : बैंकों में भी बिना दावे के 35,000 करोड़ रुपए - बगैर दावे की सेविंग और निवेश म्यूचुअल फंड के साथ-साथ लगभग सभी बैंकों और इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के लिए बड़ी समस्या है। पिछले महीने सरकार ने सरकारी बैंकों के पास करीब 35,000 करोड़ रुपए की विशाल रकम बगैर दावे की जमा होने का अनुमान लगाया था।

सपोर्ट नहीं मिलता, अर्थव्यवस्था को होता है नुकसान - अर्थव्यवस्था के लिए दिक्कत ये है कि ऐसी राशि बिना इस्तेमाल के लंबे समय तक पड़ी रहती है। इनका इस्तेमाल होने पर खपत बढ़ने और अर्थव्यवस्था को सपोर्ट मिलने की संभावना होती है। वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री भागवत कराड ने संसद में एक सवाल के जवाब में कहा, 'ताजा जानकारी के मुताबिक, फरवरी 2023 के अंत तक आरबीआई को डिपॉजिट के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा बगैर दावे वाले 35,012 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए।

न्यूज ब्रीफ

इस साल 9 करोड़ नौकरियां पैदा करेगी टूरिज्म इंडस्ट्री: देश में बढ़ रहा मेडिकल, वेलनेस, आध्यात्मिक और एडवेंचर टूरिज्म सेगमेंट

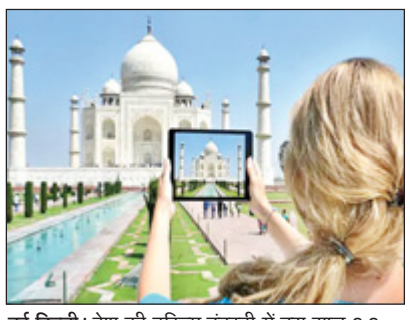

नई दिल्ली। देश की टूरिज्म इंडस्ट्री में इस साल 8.8 करोड़ नई नौकरियां पैदा होंगी। सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) में इस इंडस्ट्री का 11.48 लाख करोड़ रुपए (5प्रतिशत) का योगदान होगा। कुल नौकरियों में इस सेक्टर की 13प्रतिशत हिस्सेदारी है। अगले दशक में भारत में मेडिकल, वेलनेस, आध्यात्मिक, बिजनेस ट्रैवल के साथ एडवेंचर टूरिज्म सेगमेंट में वृद्धि होगी। डिजिटल पेमेंट कंपनी वीसा और प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म ईवाई की एक रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। 'चार्टिंग दी कोर्स फॉर इंडिया: टूरिज्म मेगाट्रेंड्स अनपैक्ड' नाम की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में विदेशी सैलानी घरेलू पर्यटकों से 26 गुना ज्यादा खर्च करते हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर ट्रैवल इंडस्ट्री के 2023 में कोविड के असर से पूरी तरह रिकवर होने की उम्मीद है। इस साल ये प्री-कोविड लेवल के 85-95प्रतिशत तक पहुंच जाएगी। इसका बड़ा फायदा भारत को भी मिलेगा। केंद्र ने 2023 के बजट में विदेश में प्रमोशनल एक्टिविटी पर खर्च में 50प्रतिशत कटौती की।

अब नाबालिग के एकाउंट में ही जाएगी निवेश की राशि, नए बैंक खाते को करना होगा अपडेट

नई दिल्ली। निवेशकों की सुरक्षा को मजबूत करते हुए सेबी ने एक नया नियम लाया है। इसने कहा कि अब नाबालिग के नाम से अगर म्यूचुअल फंड में कोई निवेश होता है तो उस रकम को निकालने के लिए नाबालिग का बैंक खाता होना जरूरी है भुगतान उसी खाते में होगा। हालांकि, निवेश नाबालिग के अभिभावक, गार्जियन के खाते, या फिर इनके संयुक्त खाते से किया जा सकता है। इसे 15 जून से लागू किया जाएगा। सेबी ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया। इसमें सभी म्यूचुअल फंडों से कहा है कि नए निवेश के तहत यह व्यवस्था तो होगी, पर पुराने में भी लागू होगी। सभी म्यूचुअल फंड कंपनियों को इसके लिए नाबालिग वाले फोलियो में नए बैंक खाते को अपडेट करना होगा। अगर किसी नाबालिग का बैंक खाता नहीं है तो उसके फोलियो में जो भी निवेश किया गया है, उसे नहीं निकाल पाएंगे। सेबी ने 2019 में यह नियम लाया था कि नाबालिग के नाम से जो भी निवेश होगा, वह गार्जियन के तहत होगा, लेकिन नाम नाबालिग का होगा। हालांकि, उस समय नाबालिग के बैंक खाते की जरूरत नहीं थी। पर बाद मे सेबी ने यह कहा कि निवेश के लिए भी नाबालिग का बैंक खाता होना जरूरी है। अब नए नियम में निवेश की रकम भुनाई जाती है तो वह केवल नाबालिग के ही बैंक खाते में जाएगी।

शेयर बाजार में महाराष्ट्र को उत्तर प्रदेश से चुनौती, एक साल में यूपी से 35 लाख नए निवेशकों ने किया प्रवेश

लखनऊ । शेयर बाजार में यूपी की ठसक लगातार बढ़ रही है। शेयर बाजार के गढ़ महाराष्ट्र को ही यूपी वालों ने सीधी टक्कर दे दी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के मुताबिक एक साल में यूपी से 35 लाख नए निवेशकों ने शेयर बाजार में प्रवेश किया है। ये संख्या महाराष्ट्र (44 लाख) के बाद सर्वाधिक है। गुजरात से 17 लाख नए निवेशकों ने प्रवेश किया है। बीएसई के मुताबिक, नए डीमैट खाते खोलने में यूपी ने महाराष्ट्र के अलावा सभी को पीछे छोड़ दिया है। एक साल में 37प्रतिशत की बढ़त हुई है। इसी अवधि में महाराष्ट्र की ग्रोथ 20प्रतिशत, गुजरात की 15प्रतिशत, राजस्थान की 26प्रतिशत और कर्नाटक की 20प्रतिशत रही है। यूपी में आय बढ़ने, महिलाओं का बाजार में रुझान और जोखिम की क्षमता प्रमुख वजहें हैं। कुल डीमैट खातों में 3.40 लाख करोड़ रुपये के शेयर जमा हैं। इसमें यूपी की हिस्सेदारी करीब 5.5प्रतिशत है। यानी डीमैट खातों में यूपी वालों के 18,700 करोड़ रुपये के शेयर सुरक्षित हैं।

भारत को शीर्ष-3 अर्थव्यवस्था में देखना सरकार का लक्ष्य, जापान और जर्मनी से ज्यादा पीछे नहीं

नई दिल्ली ।

आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2026-27 तक भारत को दुनिया की शीर्ष-3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करना है। जापान और जर्मनी से हम बहुत पीछे नहीं हैं। ऐसे में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना हमारे लक्ष्य के मुताबिक है।

उन्होंने कहा, सरकार का ध्यान अपनी बेहतर नीतियों के जरिये भारत को वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में एक गंभीर और प्रतिस्पर्धी भागीदार बनने के लिए आगे बढ़ाने पर है। एपल, सैमसंग और सिस्को जैसी कंपनियां अब भारत आ रही हैं।

निर्माण और डिजाइन में पैदा हुए अवसर

सरकार ने सिर्फ 14 महीने में निर्माण और डिजाइन में मौके पैदा किए हैं। भारत 2024 तक 100 सेमीकंडक्टर डिजाइन स्टार्टअप बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। इस क्षेत्र में जल्द 85 हजार उच्च कुशल पेशेवरों का प्रतिभा पूल होगा।

समीक्षा बैठक में लगातार घाटे में चल रहे क्षेत्रीय ग्रामीणबैंकों पर हुईचर्चा

वित्त मंत्रालय ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) से कहा कि वे वित्तीय समावेश के मामले में प्रदर्शन सुधारने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज वितरण में सुधार करें। वित्तीय सेवाओं के विभाग

के सचिव विवेक जोशी की अगुवाई में हुई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समीक्षा बैठक में इन बैंकों की वित्तीय व्यवहार्यता योजनाओं पर चर्चा की गई। इसकी वजह यह है कि कुछ आरआरबी घाटे में चल रहे हैं। बैठक के दौरान जोशी ने कहा कि आरआरबी को वित्तीय समावेश की दिशा में सरकारी प्रयासों के अनुरूप कदम उठाने होंगे। बैठक में वित्तीय सेवाओं के विभाग, आरबीआई, नाबार्ड, प्रायोजक बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आरआरबी के चेयरपर्सन भी शामिल हुए।

कार्वी के पूर्व अधिकारियों पर 1.9 करोड़ का जुर्माना

बाजार नियामक सेबी ने कार्वी समूह के चार पूर्व अधिकारियों पर 1.9 करोड़ का जुर्माना लगाया है इसका भुगतान 45 दिन में करना है। ग्राहकों की पूंजी की हेराफेरी से जुड़े मामलों में नियमों के उल्लंघन पर यह कार्रवाईकी गई है।

विदेशी मुद्रा भंडार 7.2 अरब डॉलर बढ़ा, 11 माह के शीर्ष पर

देश का विदेशी मुद्रा भंडार 5 मई को समाप्त सप्ताह में 7.2 अरब डॉलर बढ़कर 595.98 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। यह इसका 11 महीने का उच्च स्तर है। इससे पिछले सप्ताह भंडार 4.53 अरब डॉलर घटकर 588.78 अरब डॉलर के स्तर पर आ गया था। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक, 5 मई वाले सप्ताह में विदेशी मुद्रा संपत्ति 6.53 अरब डॉलर बढ़कर 526.02 अरब डॉलर पहुंच गई।सोने का भंडार 65.9 करोड़ डॉलर बढ़कर 46.31 अरब डॉलर पर पहुंच गया। देश का विदेशी मुद्रा भंडार अक्तूबर, 2021 में 645 अरब डॉलर के सार्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। उसके बाद रुपये में गिरावट रोकने के लिए आरबीआई ने डॉलर बेचना शुरू कर दिया था।

गूगल पे की भुगतान नीति की जांच करेगा प्रतिस्पर्धा आयोग, गूगल पर लगाया गया था 936 करोड़ का जुर्माना

नई दिल्ली । भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने गूगल एप पर इस्तेमाल किए जाने वाले गूगल पे की भुगतान नीतियों की जांच का आदेश जारी किया। आदेश में सीसीआई ने गूगल से गूगल पे के तहत तीसरे पक्ष के जरिये किए जाने वाले भुगतान की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए भी कहा है।

डेटिंग एप टिंडर के मालिक मैच समूह और अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन ने सीसीआई से गूगल की यूजर चॉइस बिलिंग (यूसीबी) नीति को प्रतिस्पर्धा विरोधी और अनुचित बताते हुए जांचने का अनुरोध किया था। सीसीआई ने माना कि इस मामले में जांच की जरूरत है। एप डेवलपरों की शिकायत पर सीसीआई ने पिछले वर्ष अक्तूबर में तीसरे पक्ष से भुगतान का विकल्प नहीं देने के मामले में गूगल पर 936 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।

चार सप्ताह में देना होगा जवाब

सीसीआई ने गूगल से यूसीबी से पहले और बाद में इन-ऐप भुगतान प्रणाली से संबंधित प्रावधानों को समझाने के लिए कहा है। आदेश में कहा गया है कि गूगल को चार सप्ताह में जवाब देना है। इससे पहले गूगल ने कहा था कि वह डेवलपर से सेवा शुल्क इसलिए वसूलता है, ताकि गूगल प्ले ऐप स्टोर और एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिये उनके एप मुफ्त में मुहैया कराए जा सकें और उन्हें डेवलपर टूल और एनालिटिक्स सेवा दी जा सके।

हर जिले में शीर्ष 100 जमाकर्ताओं को खोजकर बैंक देंगे पैसा, 100 दिन चलेगा अभियान

नई दिल्ली ।

बैंकों में बिना दावे वाली पड़ी अरबों रुपये की रकम के मालिकों को खोजने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अब 100 दिन का अभियान चलाएगा। इस अभियान को 100 डेज-100 पेज नाम दिया गया है। इस अभियान के तहत हर बैंक 100 दिनों के अंदर देश के हर जिले में शीर्ष 100 बिना दावे वाले जमाकर्ताओं को खोजेगा और उसका भुगतान करेगा।

आरबीआई के आदेश पर सभी बैंक एक जून से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। नियम के मुताबिक, जिस भी बचत या चालू खाता को 10 साल तक नहीं चलाया जाता है, या कोई टर्म जमा का खाता है जिसमें 10 साल तक कोई दावा नहीं करता है, ऐसे खातों में पड़ी रकम को लावारिस या बिना दावे वाली रकम माना जाता है। बैंक इन ग्राहकों से संपर्क करने की कोशिश भी करते हैं। इसके बावजूद अगर कोई दावेदार नहीं मिलता तो यह एक विशेष खाते में चली जाती है।

वित्त मंत्री सीतारमण ने दिया था निर्देश - हाल ही में एक बैठक के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बिना दावे के रकम को लेकर नियामकों से कहा था कि वे बैंकिंग शेयर, डिविडेंड, म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस के रूप में जहां भी बिना दावे वाली रकम पड़ी है, उसके निपटारे के लिए विशेष अभियान संचालित करें। आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ का कहना है कि ऐसे मामलों में जहां नामित व्यक्ति की जानकारी नहीं है, वहां निर्धारित प्रक्रिया के तहत कदम आगे बढ़ाए जाएंगे।

सरकारी बैंकों में बिना दावे के जमा हैं करीब 35,000 करोड़, सबसे ज्यादा एसबीआई में - सरकारी बैंकों में करीब 35,000 करोड़ रुपये की रकम ऐसी है जिस पर किसी ने अपना दावा नहीं किया है। सरकारी बैंकों ने इस पैसे को रिजर्व बैंक को ट्रांसफर कर दिया है। इसमें भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई में 8,086 करोड़ रुपये के लावारिस हैं। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक में 5,340 करोड़ रुपये, केनरा बैंक में 4,558 करोड़ रुपये और बैंक ऑफ बड़ौदा में 3,904 करोड़ रुपये हैं।

एलआईसी के पास भी 21 हजार करोड़ से ज्यादा - भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक, तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, कर्नाटक, बिहार, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बैंकों में बिना दावे वाली रकम सबसे ज्यादा है।

सोना 710 रुपये टूटकर 61000 से नीचे, चांदी 2,690 रुपये सस्ती

नई दिल्ली ।

वैश्विक बाजारों में बहुमूल्य धातुओं में नरमी से घरेलू बाजार में भी सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सोना 61,000 और चांदी 74,000 के स्तर से नीचे पहुंच गई। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 710 रुपये सस्ता होकर 60,970 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ। चांदी की कीमत 2,690 रुपये की बड़ी गिरावट के साथ 73,445 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुई। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 61,680 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) सौमिल गांधी ने कहा, एशियाई कारोबारी घंटों में कॉमेक्स पर पीली धातु गिरावट के साथ कारोबार कर रही थी। इससे दिल्ली सराफा बाजार में सोने की हाजिर कीमत में 710 रुपये की गिरावट देखी गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना नरमी के साथ 2,009 डॉलर प्रति औंस रह गया। चांदी भी गिरावट के साथ 25.10 डॉलर प्रति औंस पर के भाव पर कारोबार कर रही थी।

सेंसेक्स 123 अंक चढ़कर पांच महीने के उच्चतम स्तर पर बंद

वैश्विक बाजारों में कमजोरी के बावजूद सेंसेक्स पांच महीने के उच्च स्तर पर पहुंचकर बंद हुआ। बैंकिंग और वाहन कंपनियों के शेयरों में खरीदारी से घरेलू बाजार को समर्थन मिला और सेंसेक्स 123.38 अंक चढ़कर 62,027.90 पर बंद हुआ। यह सेंसेक्स का 12 दिसंबर, 2022 के बाद का उच्चतम स्तर है। निफ्टी 17.80 अंक की बढ़त के साथ 18,314.80 पर बंद हुआ। बाजार की शुरुआत कमजोर रही। दोपहर बाद बैंकिंग-वाहन कंपनियों में खरीदारी से सेंसेक्स में तेजी आई। 30 में 18 कंपनियों के शेयर बढ़त में बंद हुए।

विकास की राह पर दुनिया का भरोसा जीतने के लिए उदार लोकतंत्र जरूरी, रघुराम राजन ने दी सलाह

लंदन ।

भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन अक्सर आर्थिक जगत से जुड़ी सलाह देते नजर आते हैं। इस बार उन्होंने कहा कि भारत की वृद्धि का मार्ग इसकी भीतरी ताकत के भरपूर इस्तेमाल और सहिष्णुता एवं सबका सम्मान की ऐतिहासिक संस्कृति के दम पर खुद को वैश्विक आपूर्ति शृंखला के लिए अहम बनाने में निहित है।

उदार लोकतांत्रिक मूल्य एक आर्थिक आवश्यकता

भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर राजन ने 'आइडियाज फॉर इंडिया' सम्मेलन में अपने प्रमुख संबोधन में कहा कि भारत के पास सेवा उद्योग में

नेतृत्व की भूमिका निभाने की काबिलियत है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर बल दिया कि दुनिया का भरोसा हासिल करने के लिए देश के उदार लोकतांत्रिक मूल्य एक आर्थिक आवश्यकता हैं। उन्होंने चीन जैसे सस्ते विनिर्माण देश के साथ प्रतिस्पर्द्धा के संदर्भ में कहा कि भारत को विनिर्माण के सेवा घटक या सीधे तौर पर सेवाओं पर ध्यान देने से फायदा मिलेगा।

विनिर्माण वृद्धि पथ पर आगे जाना है

राजन ने कहा कि अगर हमें विनिर्माण सेवा-निर्देशित वृद्धि पथ पर आगे जाना है तो हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका, हमारा उदार लोकतंत्र हमें बढ़त दिलाने वाले पहलू हैं। इसकी वजह यह है कि इसके सहारे हम दुनिया का भरोसा हासिल करने में सफल रहेंगे, यह बेहद जरूरी है। चीन जैसे सस्ते विनिर्माण पड़ोसी के साथ प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में, प्रमुख अर्थशास्त्री ने कहा कि भारत एक विश्वसनीय वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में विनिर्माण या सेवाओं के सेवा घटक पर अधिक सीधे ध्यान केंद्रित करने से लाभान्वित होगा।

लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना होमवर्क करने की आवश्यकता

उन्होंने कहा कि हम भारतीयों के रूप में लोकतंत्र चाहते हैं लेकिन हम यह भी चाहते हैं कि लोकतंत्र दुनिया को यह विश्वास दिलाने में सक्षम हो कि हम पर भरोसा किया जा सकता है, कि हम इस प्रकार की सेवाओं के प्रभावी प्रदाता हो सकते हैं, हमें अपने संस्थानों को मजबूत करने, अपने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना होमवर्क करने की आवश्यकता है।

जियो सिनेमा ने लॉन्च किया सब्सक्रिप्शन प्लान

999 रुपए में सालभर ले सकेंगे इसका मजा, एक साथ 4 डिवाइस पर देख सकेंगे कंटेंट

नई दिल्ली ।

जियो सिनेमा ने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च कर दिया है। यानी आपको जियो सिनेमा के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के लिए भी अमेजन प्राइम वीडियो, डिज्नी+ हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स के की तरह सब्सक्रिप्शन लेना होगा। जियो सिनेमा ने अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमत 999 रुपए रखी है। इस प्लान के तहत कंपनी यूजर्स को 12 महीनों के लिए जियो सिनेमा का सब्सक्रिप्शन मिलेगा।

एक साथ 4 डिवाइस में कर सकेंगे लॉग-इन

जियो सिनेमा ऐप पर जल्द ही गेम ऑफ थ्रोन्स, हैरी पोटर, सक्सेशन और डिस्कवरी जैसे मूवी और शोज देख सकेंगे। इस प्लान के तहत यूजर्स अपने अकाउंट को एक साथ 4 डिवाइस में लॉग-इन कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर दी गई जानकारी के अनुसार जियो सिनेमा

ऐप को अब तक 10 करोड़ से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है।

इस पर देख सकेंगे गेम ऑफ थ्रोन्स और हैरी पोटर

जियो सिनेमा के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर गेम ऑफ थ्रोन्स, हैरी पोटर, सक्सेशन और डिस्कवरी जैसे मूवी और शोज देख सकेंगे। इसके लिए मुकेश अंबानी की कंपनी वायाकॉम18 ने हॉलीवुड के जाने-माने प्रोडक्शन हाउस वॉर्नर ब्रदर्स के साथ डील की है। इस डील के बाद जियो सिनेमा अमेजन प्राइम वीडियो और डिज्नी हॉटस्टार को सीधी टक्कर देगा।

वायाकॉम 18 और वार्नर ब्रदर्स ने कहा, जियो सिनेमा पर फिल्में और शो के प्रीमियर अमेरिका के साथ ही होंगे। इससे पहले, डिज्नी के पास वार्नर ब्रदर्स और एचबीओ के कंटेंट को स्ट्रीम के अधिकार थे। यह पार्टनरशिप 31 मार्च 23 को खत्म हो गई। इस कारण भारतीय दर्शक एचबीओ के गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे शोज स्ट्रीम नहीं कर पा रहे थे। वार्नर ब्रदर्स एचबीओ की पैरेंट कंपनी है।

फ्री में आईपीएल दिखा रहा जियो

इस बार 4के क्वालिटी में आईपीएल की फ्री में लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। जियो सिनेमा आईपीएल 2023 का ऑफिशियल लाइव-स्ट्रीमिंग पार्टनर है। इससे पहले तक आईपीएल डिज्नी हॉटस्टार पर दिखाया जाता था। ऐसे में इसे देखने के लिए हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था। अभी जियो सिनेमा पर कुछ भी देखने के लिए आपको कोई फीस नहीं चुकानी होती।

जियो सिनेमा को एंटरटेनमेंट का सबसे मैंगनेटिक डेस्टिनेशन बनाने का मिशन

वायाकॉम 18 में सब्सक्रिप्शन वीडियो-ऑन-डिमांड और इंटरनेशनल बिजनेस के हेड फरजाद पालिया ने कहा कि जियो सिनेमा लाइव स्पोर्ट्स के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। अब हम जियो सिनेमा को एंटरटेनमेंट का सबसे मैंगनेटिक डेस्टिनेशन बनाने के मिशन पर हैं।

एससीओ देशों की बैठक में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, भारत के इस प्रस्ताव को मंजूरी

नई दिल्ली । एससीओ के सदस्य देशों के बीच आईसीटी के विकास के लिए जिम्मेदार मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से सदस्य देशों में डिजिटल प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को विकसित करने के भारत के प्रस्ताव को अपनाया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक में शामिल होने के बाद बताया कि यह डीपीआई प्रतिस्पर्धा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और यह सुनिश्चित करता है कि प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण किया जाए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सदस्य राज्यों के बीच डिजिटल रूप से समावेशी विकास हो।

मेसर्स दैनिक नईदुनिया के लिए प्रकाशक अपूर्व तिवारी के द्वारा 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल- 462011 से प्रकाशित एवं मुद्रक डॉ. विश्वास तिवारी के द्वारा नईदुनिया प. प्रा.लि., 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल-462011 से मुद्रित। प्रबंध संपादक: डॉ. सुरेन्द्र तिवारी एवं संपादक: अपूर्व तिवारी। *
फोन-0755-2550900-01,-03, फैक्स नं.- 0755-2553914 e-mail : naidunia@gmail.com (* समाचार पत्र से संबंधित सभी प्रकार के विवादों के लिए न्याय क्षेत्र सिर्फ भोपाल होगा।) रजिस्टर्ड नं.म.प्र./296/भोपाल/2012-2014 आर.एन.आई. रजि. क्र. 47694/88, डाक पंजीयन क्र. म.प्र./भोपाल/296/2015-2017